

# Rise Of Popular Movements जन आंदोलनों का उदय

## In this chapter...

**Three decades after Independence, the people were beginning to get impatient. Their unease expressed itself in various forms. In the previous chapter, we have already gone through the story of electoral upheavals and political crisis.**

## इस अध्याय में...

आज़ादी के तीन दशक बाद लोगों का धीरज टूटने लगा था। जनता की बेचैनी कई रूपों में अभिव्यक्त हुई। पिछले अध्याय में हम चुनावी भूचाल और राजनीतिक संकट के बारे में पढ़ ही चुके हैं।

# Rise Of Popular Movements जन आंदोलनों का उदय

**Yet that was not the only form in which popular discontent expressed itself. In the 1970s, diverse social groups like women, students, Dalits and farmers felt that democratic politics did not address their needs and demands. Therefore, they came together under the banner of various social organisations to voice their demands. These assertions marked the rise of popular movements or new social movements in Indian politics**

बहरहाल, जन-असंतोष की अभिव्यक्ति सिर्फ इसी रूप में ही नहीं हुई। 1970 के दशक में विभिन्न सामाजिक वर्गों जैसे—महिला, छात्र, दलित और किसानों को लग रहा था कि लोकतांत्रिक राजनीति उनकी ज़रूरत और माँगों पर ध्यान नहीं दे रही है। इसके चलते ये समूह अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए विभिन्न सामाजिक संगठनों के झंडे के नीचे एकजुट हुए। इन आवाज़ों से जन आंदोलन का ज्वार उमड़ा और भारतीय राजनीति में नए सामाजिक आंदोलन सक्रिय हुए।

# **Rise Of Popular Movements जन आंदोलनों का उदय**

**In this chapter we trace the journey of some of the popular movements that developed after the 1970s in order to understand:**

- **what are popular movements?**
- **which sections of Indian society have they mobilised?**
- **what is the main agenda of these movements?**
- **what role do they play in a democratic set up like ours?**

इस अध्याय में हम 1970 के दशक के बाद के जन आंदोलनों की विकास-यात्रा को परखने की कोशिश करेंगे। इस चर्चा से हम समझ सकेंगे कि :

- जन आंदोलन क्या हैं?
- भारतीय समाज के किन तबकों को इन आंदोलनों ने लामबंद किया है?
- हमारे लोकतांत्रिक ढाँचे में ये जन आंदोलन क्या भूमिका निभाते हैं?

# Rise Of Popular Movements जन आंदोलनों का उदय

## Nature of popular movements

**Take a look at the opening image of this chapter. What do you see there? Villagers have literally embraced the trees. Are they playing some game? Or participating in some ritual or festival? Not really. The image here depicts a very unusual form of collective action in which men and women from a village in what is now Uttarakhand were engaged in early 1973.**

## जन आंदोलनों की प्रकृति

इस अध्याय के शुरुआती चित्र पर ध्यान दीजिए। आप इसमें क्या देख रहे हैं? गाँव की महिलाओं ने सचमुच पेड़ों को अपनी बाँहों में बाँध रखा है। क्या ये लोग कोई खेल खेल रहे हैं या, ये लोग कोई पर्व-त्योहार मना रहे हैं? दरअसल चित्र में नज़र आ रहे लोग ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ जो तस्वीर दी गई है उसमें सामूहिक कार्रवाई की एक असाधारण घटना को दर्ज़ किया गया है। यह घटना 1973 में घटी जब मौजूदा उत्तराखंड के एक गाँव के स्त्री-पुरुष एकजुट हुए और जंगलों की व्यावसायिक कटाई का विरोध किया।

# **Rise Of Popular Movements** जन आंदोलनों का उदय

**These villagers were protesting against the practices of commercial logging that the government had permitted. They used a novel tactic for their protest – that of hugging the trees to prevent them from being cut down. These protests marked the beginning of a world-famous environmental movement in our country – the Chipko movement.**

सरकार ने जंगलों की कटाई के लिए अनुमति दी थी। गाँव के लोगों ने अपने विरोध को जताने के लिए एक नयी तरकीब अपनायी। इन लोगों ने पेड़ों को अपनी बाँहों में घेर लिया ताकि उन्हें कटने से बचाया जा सके। यह विरोध आगामी दिनों में भारत के पर्यावरण आंदोलन के रूप में परिणत हुआ और 'चिपको-आंदोलन' के नाम से विश्वप्रसिद्ध हुआ।

# Rise Of Popular Movements जन आंदोलनों का उदय

## Chipko movement

**The movement began in two or three villages of Uttarakhand when the forest department refused permission to the villagers to fell ash trees for making agricultural tools. However, the forest department allotted the same patch of land to a sports manufacturer for commercial use. This enraged the villagers and they protested against the move of the government. The struggle soon spread across many parts of the Uttarakhand region.**

## चिपको आंदोलन

इस आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के दो-तीन गाँवों से हुई थी। इसके पीछे एक कहानी है। गाँव वालों ने वन विभाग से कहा कि खेती-बाड़ी के औज़ार बनाने के लिए हमें अंगू के पेड़ काटने की अनुमति दी जाए। वन विभाग ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। बहरहाल, विभाग ने खेल-सामग्री के एक विनिर्माता को ज़मीन का यही टुकड़ा व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए आबंटित कर दिया। इससे गाँव वालों में रोष पैदा हुआ और उन्होंने सरकार के इस कदम का विरोध किया। यह विरोध बड़ी जल्दी उत्तराखंड के अन्य इलाकों में भी फैल गया।

# Rise Of Popular Movements जन आंदोलनों का उदय

**Larger issues of ecological and economic exploitation of the region were raised. The villagers demanded that no forest-exploiting contracts should be given to outsiders and local communities should have effective control over natural resources like land, water and forests. They wanted the government to provide low cost materials to small industries and ensure development of the region without disturbing the ecological balance. The movement took up economic issues of landless forest workers and asked for guarantees of minimum wage.**

क्षेत्र की पारिस्थितिकी और आर्थिक शोषण के कहीं बड़े सवाल उठने लगे। गाँववासियों ने माँग की कि जंगल की कटाई का कोई भी ठेका बाहरी व्यक्ति को नहीं दिया जाना चाहिए और स्थानीय लोगों का जल, जंगल, जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर कारगर नियंत्रण होना चाहिए। लोग चाहते थे कि सरकार लघु-उद्योगों के लिए कम कीमत की सामग्री उपलब्ध कराए और इस क्षेत्र के पारिस्थितिकी संतुलन को नुकसान पहुँचाए बगैर यहाँ का विकास सुनिश्चित करे। आंदोलन ने भूमिहीन वन कर्मचारियों का आर्थिक मुद्दा भी उठाया और न्यूनतम मजदूरी की गारंटी की माँग की।

# Rise Of Popular Movements जन आंदोलनों का उदय

**Women's active participation in the Chipko agitation was a very novel aspect of the movement. The forest contractors of the region usually doubled up as suppliers of alcohol to men. Women held sustained agitations against the habit of alcoholism and broadened the agenda of the movement to cover other social issues. The movement achieved a victory when the government issued a ban on felling of trees in the Himalayan regions for fifteen years, until the green cover was fully restored.**

चिपको आंदोलन में महिलाओं ने सक्रिय भागीदारी की। यह आंदोलन का एकदम नया पहलू था। इलाके में सक्रिय जंगल कटाई के ठेकेदार यहां के पुरुषों को शराब की आपूर्ति का भी व्यवसाय करते थे। महिलाओं ने शराबखोरी की लत के खिलाफ भी लगातार आवाज़ उठायी। इससे आंदोलन का दायरा विस्तृत हुआ और उसमें कुछ और सामाजिक मसले आ जुड़े। आखिरकार इस आंदोलन को सफलता मिली और सरकार ने पंद्रह सालों के लिए हिमालयी क्षेत्र में पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी ताकि इस अवधि में क्षेत्र का वनाच्छादन फिर से ठीक अवस्था में आ जाए।



# Rise Of Popular Movements जन आंदोलनों का उदय

**But more than that, the Chipko movement, which started over a single issue, became a symbol of many such popular movements emerging in different parts of the country during the 1970s and later. In this chapter we shall study some of these movements.**

बहरहाल, बात इस आंदोलन की सफलता की तो है ही, साथ ही हमें यह भी याद रखना होगा कि यह आंदोलन सत्तर के दशक और उसके बाद के सालों में देश के विभिन्न भागों में उठे अनेक जन आंदोलनों का प्रतीक बन गया। इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे।

# Rise Of Popular Movements जन आंदोलनों का उदय

## Party based movements

**Popular movements may take the form of social movements or political movements and there is often an overlap between the two. The nationalist movement, for example, was mainly a political movement. But we also know that deliberations on social and economic issues during the colonial period gave rise to independent social movements like the anti-caste movement, the kisan sabhas and the trade union movement in early twentieth century. These movements raised issues related to some underlying social conflicts.**

## दल-आधारित आंदोलन

जन आंदोलन कभी सामाजिक तो कभी राजनीतिक आंदोलन का रूप ले सकते हैं और अक्सर ये आंदोलन दोनों ही रूपों के मेल से बने नज़र आते हैं। उदाहरण के लिए, हम अपने स्वाधीनता आंदोलन को ही लें। यह मुख्य रूप से राजनीतिक आंदोलन था लेकिन हम जानते हैं कि औपनिवेशिक दौर में सामाजिक-आर्थिक मसलों पर भी विचार मंथन चला जिससे अनेक स्वतंत्र सामाजिक आंदोलनों का जन्म हुआ, जैसे-जाति प्रथा विरोधी आंदोलन, किसान सभा आंदोलन और मज़दूर संगठनों के आंदोलन। ये आंदोलन बीसवीं सदी के शुरुआती दशकों में अस्तित्व में आए। इन आंदोलनों ने सामाजिक संघर्षों के कुछ अंदरूनी मुद्दे उठाए।

# **Rise Of Popular Movements जन आंदोलनों का उदय**

**Some of these movements continued in the post-independence period as well. Trade union movement had a strong presence among industrial workers in major cities like Mumbai, Kolkata and Kanpur. All major political parties established their own trade unions for mobilising these sections of workers. Peasants in the Telangana region of Andhra Pradesh organised massive agitations under the leadership of Communist parties in the early years of independence and demanded redistribution of land to cultivators.**

एसे कुछ आंदोलन आज़ादी के बाद के दौर में भी चलते रहे। मुंबई, कोलकाता और कानपुर जैसे बड़े शहरों के औद्योगिक मज़दूरों के बीच मज़दूर संगठनों के आंदोलन का बड़ा ज़ोर था। सभी बड़ी पार्टियों ने इस तबके के मज़दूरों को लामबंद करने के लिए अपने-अपने मज़दूर संगठन बनाए। आज़ादी के बाद के शुरुआती सालों में आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र के किसान कम्युनिस्ट पार्टियों के नेतृत्व में लामबंद हुए। इन्होंने काश्तकारों के बीच ज़मीन के पुनर्वितरण की माँग की।

# Rise Of Popular Movements जन आंदोलनों का उदय

**Peasants and agricultural labourers in parts of Andhra Pradesh, West Bengal, Bihar and adjoining areas continued their agitations under the leadership of the Marxist-Leninist workers; who were known as the Naxalites (you have already read about the Naxalite movement in the last chapter). The peasants' and the workers' movements mainly focussed on issues of economic injustice and inequality.**

आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ भागों में किसान तथा खेतिहर मजदूरों ने मार्क्सवादी-लेनिनवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में अपना विरोध जारी रखा। आप मार्क्सवादी-लेनिनवादी समूहों के बारे में पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। इन्हें 'नक्सलवादी' के नाम से जाना गया। किसान और मजदूरों के आंदोलन का मुख्य जोर आर्थिक अन्याय तथा असमानता के मसले पर रहा। ऐसे आंदोलनों ने औपचारिक रूप से चुनावों में भाग तो नहीं लिया लेकिन राजनीतिक दलों से इनका नज़दीकी रिश्ता कायम हुआ। इन आंदोलनों में शरीक कई व्यक्ति और संगठन राजनीतिक दलों से सक्रिय रूप से जुड़े। ऐसे जुड़ावों से दलगत राजनीति में विभिन्न सामाजिक तबकों की बेहतर नुमाइंदगी सुनिश्चित हुई।

# Rise Of Popular Movements जन आंदोलनों का उदय

## Non-party movements

In the 1970s and 1980s, many sections of the society became disillusioned with the functioning of political parties. Failure of the Janata experiment and the resulting political instability were the immediate causes. But in the long run the disillusionment was also about economic policies of the state. The model of planned development that we adopted after Independence was based on twin goals of growth and distribution.

## राजनीतिक दलों से स्वतंत्र आंदोलन

‘सत्तर’ और ‘अस्सी’ के दशक में समाज के कई तबकों का राजनीतिक दलों के आचार-व्यवहार से मोहभंग हुआ। इसका तात्कालिक कारण तो यही था कि जनता पार्टी के रूप में गैर-कांग्रेसवाद का प्रयोग कुछ खास नहीं चल पाया और इसकी असफलता से राजनीतिक अस्थिरता का माहौल भी कायम हुआ था। लेकिन, अगर कारणों की खोज ज़रा दूर तक करें तो पता चलेगा कि सरकार की आर्थिक नीतियों से भी लोगों का मोहभंग हुआ था। देश ने आज़ादी के बाद नियोजित विकास (Planned Development) का मॉडल अपनाया था। इस मॉडल को अपनाने के पीछे दो लक्ष्य थे—आर्थिक संवृद्धि और आय का समतापूर्ण बँटवारा।

# Rise Of Popular Movements जन आंदोलनों का उदय

**You have read about it in Chapter Three. In spite of the impressive growth in many sectors of economy in the first twenty years of independence, poverty and inequalities persisted on a large scale. Benefits of economic growth did not reach evenly to all sections of society. Existing social inequalities like caste and gender sharpened and complicated the issues of poverty in many ways. There also existed a gulf between the urban-industrial sector and the rural agrarian sector. A sense of injustice and deprivation grew among different groups.**

आप इसके बारे में तीसरे अध्याय में पढ़ चुके हैं। आज़ादी के शुरुआती 20 सालों में अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में उल्लेखनीय संवृद्धि हुई, लेकिन इसके बावजूद गरीबी और असमानता बड़े पैमाने पर बरकरार रही। आर्थिक संवृद्धि के लाभ समाज के हर तबके को समान मात्रा में नहीं मिले। जाति और लिंग पर आधारित सामाजिक असमानताओं ने गरीबी के मसले को और ज़्यादा जटिल तथा धारदार बना दिया। शहरी-औद्योगिक क्षेत्र तथा ग्रामीण कृषि-क्षेत्र के बीच भी एक न पाटी जा सकने वाली फाँक पैदा हुई। समाज के विभिन्न समूहों के बीच अपने साथ हो रहे अन्याय और वंचना का भाव प्रबल हुआ।

# Rise Of Popular Movements जन आंदोलनों का उदय

**Many of the politically active groups lost faith in existing democratic institutions and electoral politics. They therefore chose to step outside of party politics and engage in mass mobilisation for registering their protests. Students and young political activists from various sections of the society were in the forefront in organising the marginalised sections such as Dalits and Adivasis. The middle class young activists launched service organisations and constructive programmes among rural poor. Because of the voluntary nature of their social work, many of these organisations came to be known as voluntary organisations or voluntary sector organisations.**

राजनीतिक धरातल पर सक्रिय कई समूहों का विश्वास लोकतांत्रिक संस्थाओं और चुनावी राजनीति से उठ गया। ये समूह दलगत राजनीति से अलग हुए और अपने विरोध को स्वर देने के लिए इन्होंने आवाज को लामबंद करना शुरू किया। इस काम में छात्र तथा समाज के विभिन्न तबकों के राजनीतिक कार्यकर्ता आगे आए और दलित तथा आदिवासी जैसे हाशिए पर धकेल दिए गए समूहों को लामबंद करना शुरू किया। मध्यवर्ग के युवा कार्यकर्ताओं ने गाँव के गरीब लोगों के बीच रचनात्मक कार्यक्रम तथा सेवा संगठन चलाए। इन संगठनों के सामाजिक कार्यों की प्रकृति स्वयंसेवी थी इसलिए इन संगठनों को स्वयंसेवी संगठन या स्वयंसेवी क्षेत्र के संगठन कहा गया।



# Rise Of Popular Movements जन आंदोलनों का उदय

**These voluntary organisations chose to remain outside party politics. They did not contest elections at the local or regional level nor did they support any one political party. Most of these groups believed in politics and wanted to participate in it, but not through political parties. Hence, these organisations were called 'non-party political formations'. They hoped that direct and active participation by local groups of citizens would be more effective in resolving local issues than political parties. It was also hoped that direct participation by people will reform the nature of democratic government.**

एसे स्वयंसेवी संगठनों ने अपने को दलगत राजनीति से दूर रखा। स्थानीय अथवा क्षेत्रीय स्तर पर ये संगठन न तो चुनाव लड़े और न ही इन्होंने किसी एक राजनीतिक दल को अपना समर्थन दिया। एसे अधिकांश संगठन राजनीति में विश्वास करते थे और उसमें भागीदारी भी करना चाहते थे, लेकिन इन्होंने राजनीतिक भागीदारी के लिए राजनीतिक दलों को नहीं चुना। इसी कारण इन संगठनों को 'स्वतंत्र राजनीतिक संगठन' कहा जाता है। इन संगठनों का मानना था कि स्थानीय मसलों के समाधान में स्थानीय नागरिकों की सीधी और सक्रिय भागीदारी राजनीतिक दलों की अपेक्षा कहीं ज्यादा कारगर होगी। इन संगठनों का विश्वास था कि लोगों की सीधी भागीदारी से लोकतांत्रिक सरकार की प्रकृति में सुधार आएगा।



# Rise Of Popular Movements जन आंदोलनों का उदय

**Such voluntary sector organisations still continue their work in rural and urban areas. However, their nature has changed. Of late many of these organisations are funded by external agencies including international service agencies. The ideal of local initiatives is weakened as a result of availability of external funds on a large scale to these organisations.**

अब भी ऐसे स्वयंसेवी संगठन शहरी और ग्रामीण इलाकों में लगातार सक्रिय हैं। बहरहाल, अब इनकी प्रकृति बदल गई है। बाद के समय में ऐसे अनेक संगठनों का वित्त-पोषण विदेशी एजेंसियों से होने लगा। ऐसी एजेंसियों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सर्विस-एजेंसियां भी शामिल हैं। इन संगठनों को बड़े पैमाने पर अब विदेशी धनराशि प्राप्त होती है जिससे स्थानीय पहल का आदर्श कुछ कमजोर हुआ है।

# Rise Of Popular Movements जन आंदोलनों का उदय

## Dalit Panthers

**Read this poem by well-known Marathi poet Namdeo Dhasal. Do you know who these 'pilgrims of darkness' in this poem are and who the 'sunflower-giving fakir' was that blessed them? The pilgrims were the Dalit communities who had experienced brutal caste injustices for a long time in our society and the poet is referring to Dr. Ambedkar as their liberator. Dalit poets in Maharashtra wrote many such poems during the decade of seventies.**

## दलित पैंथर्स

मराठी के प्रसिद्ध कवि नामदेव ढसाल की इस कविता को पढ़िए। क्या आप बता सकते हैं कि इस कविता में आए 'अँधेरे की पथयात्रा' और 'सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर' के क्या अर्थ हैं? 'अँधेरे की पथयात्रा' से संकेत दलित समुदाय की ओर किया गया है। इस समुदाय ने हमारे समाज में लंबे समय तक क्रूरतापूर्ण जातिगत अन्याय को भुगता है। कवि ने इस समुदाय के मुक्तिदाता डॉ. अंबेडकर को इंगित करने के लिए 'सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर' पद का प्रयोग किया है। महाराष्ट्र के दलित-कवियों ने सत्तर के दशक में ऐसी अनेक कविताएँ लिखीं।

# Rise Of Popular Movements जन आंदोलनों का उदय

**These poems were expressions of anguish that the Dalit masses continued to face even after twenty years of independence. But they were also full of hope for the future, a future that Dalit groups wished to shape for themselves. You are aware of Dr. Ambedkar's vision of socio-economic change and his relentless struggle for a dignified future for Dalits outside the Hindu caste-based social structure. It is not surprising that Dr. Ambedkar remains an iconic and inspirational figure in much of Dalit liberation writings.**

आज़ादी के बीस साल बाद भी दलित समुदाय को पीड़ा के अनुभवों से गुज़रना पड़ रहा था और उनकी इस पीड़ा तथा आक्रोश की अभिव्यक्ति इन कविताओं में हुई। बहरहाल, दलित समुदाय अपने लिए एक सुंदर भविष्य की आशा से भरा हुआ था— एक ऐसा भविष्य जिसे दलित समुदाय स्वयं अपने हाथों से गढ़े। आप सामाजिक-आर्थिक बदलावों को लेकर डॉ. अंबेडकर के स्वप्न और हिंदू जाति-व्यवस्था के ढाँचे से बाहर दलितों को एक गरिमापूर्ण सीन दिलाने के उनके जुझारू संघर्ष की बातों को जान चुके हैं। ऐसे में आश्चर्य नहीं कि दलित मुक्ति से प्रेरित अधिकांश रचनाओं में डॉ. अंबेडकर का वर्णन एक प्रेरणा-पुरुष के रूप में मिलता है।

# Rise Of Popular Movements जन आंदोलनों का उदय

## Origins

**By the early nineteen seventies, the first generation Dalit graduates, especially those living in city slums began to assert themselves from various platforms. Dalit Panthers, a militant organisation of the Dalit youth, was formed in Maharashtra in 1972 as a part of these assertions.**

## उदय

सातवें दशक के शुरुआती सालों से शिक्षित दलितों की पहली पीढ़ी ने अनेक मंचों से अपने हक की आवाज़ उठायी। इनमें ज्यादातर शहर की झुग्गी-बस्तियों में पलकर बड़े हुए दलित थे। दलित हितों की दावेदारी के इसी क्रम में महाराष्ट्र में 1972 में दलित युवाओं का एक संगठन 'दलित पैंथर्स' बना।

# Rise Of Popular Movements जन आंदोलनों का उदय

**In the post-Independence period, Dalit groups were mainly fighting against the perpetual caste based inequalities and material injustices that the Dalits faced in spite of constitutional guarantees of equality and justice. Effective implementation of reservations and other such policies of social justice was one of their prominent demands.**

आज़ादी के बाद के सालों में दलित समूह मुख्यतया जाति-आधारित असमानता और भौतिक साधनों के मामले में अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ रहे थे। वे इस बात को लेकर सचेत थे कि संविधान में जाति-आधारित किसी भी तरह के भेदभाव के विरुद्ध गारंटी दी गई है। आरक्षण के कानून तथा सामाजिक न्याय की ऐसी ही नीतियों का कारगर क्रियान्वयन इनकी प्रमुख माँग थी।

# **Rise Of Popular Movements** जन आंदोलनों का उदय

**You know that the Indian Constitution abolished the practice of untouchability. The government passed laws to that effect in the 1960s and 1970s. And yet, social discrimination and violence against the ex-untouchable groups continued in various ways. Dalit settlements in villages continued to be set apart from the main village. They were denied access to common source of drinking water.**

आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में छुआछूत की प्रथा को समाप्त कर दिया गया है। सरकार ने इसके अंतर्गत 'साठ' और 'सत्तर' के दशक में कानून बनाए। इसके बावजूद पुराने जमाने में जिन जातियों को अछूत माना गया था, उनके साथ इस नए दौर में भी सामाजिक भेदभाव तथा हिंसा का बरताव कई रूपों में जारी रहा। दलितों की बस्तियां मुख्य गाँव से अब भी दूर होती थीं।

# Rise Of Popular Movements जन आंदोलनों का उदय

**Dalit women were dishonoured and abused and worst of all, Dalits faced collective atrocities over minor, symbolic issues of caste pride. Legal mechanisms proved inadequate to stop the economic and social oppression of Dalits. On the other hand, political parties supported by the Dalits, like the Republican Party of India, were not successful in electoral politics. These parties always remained marginal; had to ally with some other party in order to win elections and faced constant splits. Therefore the Dalit Panthers resorted to mass action for assertion of Dalits' rights.**

दलित महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होते थे। जातिगत प्रतिष्ठा की छोटी-मोटी बात को लेकर दलितों पर सामूहिक जुल्म ढाये जाते थे। दलितों के सामाजिक और आर्थिक उत्पीड़न को रोक पाने में कानून की व्यवस्था नाकाफ़ी साबित हो रही थी। दूसरी तरफ़, दलित जिन राजनीतिक दलों का समर्थन कर रहे थे जैसे—रिपब्लिकन पार्टी ऑफ़ इंडिया, वे चुनावी राजनीति में सफल नहीं हो पा रही थीं। ये पार्टियां हाशिए पर रहती थीं, चुनाव जीतने के लिए इन्हें किसी दूसरी पार्टी के साथ गठजोड़ करना पड़ता था। ये पार्टियां लगातार टूट की भी शिकार हुईं इनवजहों से 'दलित पैंथर्स' ने दलित अधिकारों की दावेदारी करते हुए जन-कार्रवाई का रास्ता अपनाया।



# Rise Of Popular Movements जन आंदोलनों का उदय

## Activities

**Activities of Dalit Panthers mostly centred around fighting increasing atrocities on Dalits in various parts of the State. As a result of sustained agitations on the part of Dalit Panthers along with other like minded organisations over the issue of atrocities against Dalits, the government passed a comprehensive law in 1989 that provided for rigorous punishment for such acts. The larger ideological agenda of the Panthers was to destroy the caste system and to build an organisation of all oppressed sections like the landless poor peasants and urban industrial workers along with Dalits.**

## गतिविधि

महाराष्ट्र के विभिन्न इलाकों में दलितों पर बढ़ रहे अत्याचार से लड़ना दलित पैंथर्स की अन्य मुख्य गतिविधि थी। दलित पैंथर्स तथा इसके समधर्मा संगठनों ने दलितों पर हो रहे अत्याचार के मुद्दे पर लगातार विरोध आंदोलन चलाया। इसके परिणामस्वरूप सरकार ने 1989 में एक व्यापक कानून बनाया। इस कानून के अंतर्गत दलित पर अत्याचार करने वाले के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया गया। दलित पैंथर्स का बृहत्तर विचारधारात्मक एजेंडा जाति प्रथा को समाप्त करना तथा भूमिहीन गरीब किसान, शहरी औद्योगिक मजदूर और दलित सहित सारे वंचित वर्गों का एक संगठन खड़ा करना था।



# Rise Of Popular Movements जन आंदोलनों का उदय

**The movement provided a platform for Dalit educated youth to use their creativity as a protest activity. Dalit writers protested against the brutalities of the caste system in their numerous autobiographies and other literary works published during this period. These works portraying the life experiences of the most downtrodden social sections of Indian society sent shock waves in Marathi literary world, made literature more broad based and representative of different social sections and initiated contestations in the cultural realm.**

इस आंदोलन से पढ़-लिखे दलित युवकों को एक मंच मिला जहां वे अपनी सर्जनशीलता का उपयोग प्रतिरोध की आवाज़ बनाकर कर सकते थे। इस दौर में अनेक आत्मकथाएँ तथा अन्य साहित्य रचनाएँ प्रकाशित हुईं। इन रचनाओं में दलित लेखकों ने जाति-प्रथा की क्रूरता की ज़बर्दस्त मुखालफ़त की। भारतीय समाज के सबसे दबे-कुचले तबके के जीवन के अनुभव इन रचनाओं में दर्ज थे। इन रचनाओं से मराठी भाषा के साहित्य में ज़बर्दस्त हिलोर उठी। साहित्य का दायरा अब ज़्यादा विस्तृत हुआ। उसमें समाज के विभिन्न वर्गों की नुमाइंदगी हुई और संस्कृति के धरातल पर एक टकराहट की शुरुआत हुई।

# **Rise Of Popular Movements जन आंदोलनों का उदय**

**In the postEmergency period, Dalit Panthers got involved in electoral compromises; it also underwent many splits, which led to its decline.**

**Organisations like the Backward and Minority Communities' Employees Federation (BAMCEF) took over this space.**

आपातकाल के बाद के दौर में दलित पैंथर्स ने चुनावी समझौते किए। उसमें कई विभाजन भी हुए और यह संगठन राजनीतिक पतन का शिकार हुआ। **Backward and Minority Communities' Employees Federation (BAMCEF)** ने दलित पैंथर्स की अवनति से उत्पन्न रिक्त स्थान की पूर्ति की।

# Rise Of Popular Movements जन आंदोलनों का उदय

## **Bharatiya Kisan Union**

**The social discontent in Indian society since the seventies was manifold. Even those sections that partially benefited in the process of development had many complaints against the state and political parties. Agrarian struggles of the eighties is one such example where better off farmers protested against the policies of the state.**

## **भारतीय किसान यूनियन**

सत्तर के दशक से भारतीय समाज में कई तरह के असंतोष पैदा हुए। यहाँ तक कि समाज के जिन तबकों को विकास प्रक्रिया में कुछ लाभ हुआ था उनमें भी सरकार और राजनीतिक दलों के प्रति नाराज़गी थी। अस्सी के दशक का कृषक-संघर्ष इसका एक उदाहरण है जब अपेक्षाकृत धनी किसानों ने सरकार की नीतियों का विरोध किया।

# Rise Of Popular Movements जन आंदोलनों का उदय

## Growth

**In January 1988, around twenty thousand farmers had gathered in the city of Meerut, Uttar Pradesh. They were protesting against the government decision to increase electricity rates. The farmers camped for about three weeks outside the district collector's office until their demands were fulfilled. It was a very disciplined agitation of the farmers and all those days they received regular food supply from the nearby villages.**

## उदय

1988 के जनवरी में उत्तर प्रदेश के एक शहर मेरठ में लगभग बीस हजार किसान जमा हुए। ये किसान सरकार द्वारा बिजली की दर में की गई बढ़ोतरी का विरोधी कर रहे थे। किसान ज़िला समाहर्ता के दफ्तर के बाहर तीन हफ्तों तक डेरा डाले रहे। इसके बाद इनकी माँग मान ली गई। किसानों का यह बड़ा अनुशासित धरना था और जिन दिनों वे धरने पर बैठे थे उन दिनों आस-पास के गाँवों से उन्हें निरंतर राशन-पानी मिलता रहा।

# Rise Of Popular Movements जन आंदोलनों का उदय

**The Meerut agitation was seen as a great show of rural power – power of farmer cultivators. These agitating farmers were members of the Bharatiya Kisan Union (BKU), an organisation of farmers from western Uttar Pradesh and Haryana regions. The BKU was one of the leading organisations in the farmers' movement of the eighties.**

मेरठ के इस धरने को ग्रामीण शक्ति का या कहें कि काश्तकारों की शक्ति का एक बड़ा प्रदर्शन माना गया। धरने पर बैठे किसान, भारतीय किसान यूनियन (BKU), के सदस्य थे। बीकेयू पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के किसानों का एक संगठन था। यह अस्सी के दशक के किसान आंदोलन के अग्रणी संगठनों में एक था।

# Rise Of Popular Movements जन आंदोलनों का उदय

**We have noted in Chapter Three that farmers of Haryana, Punjab and western Uttar Pradesh had benefited in the late 1960s from the state policies of 'green revolution'. Sugar and wheat became the main cash crops in the region since then. The cash crop market faced a crisis in mid-eighties due to the beginning of the process of liberalisation of Indian economy.**

तीसरे अध्याय में आपने पढ़ा था कि सरकार ने जब 'हरित क्रांति' की नीति अपनाई तो 1960 के दशक के अंतिम सालों से हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को फ़ायदा होना शुरू हो गया। इसके बाद के सालों से इन इलाकों में गन्ना और गेहूँ मुख्य नगदी फ़सल बने। 1980 के दशक के उत्तरार्ध से भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के प्रयास हुए और इस क्रम में नगदी फ़सल के बाज़ार को संकट का सामना करना पड़ा।

# **Rise Of Popular Movements** जन आंदोलनों का उदय

**The BKU demanded higher government floor prices for sugarcane and wheat, abolition of restrictions on the inter-state movement of farm produce, guaranteed supply of electricity at reasonable rates, waiving of repayments due on loans to farmers and the provision of a government pension for farmers.**

भारतीय किसान यूनियन ने गन्ने और गेहूं के सरकारी खरीद मूल्य में बढ़ोतरी करने, कृषि उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवाजाही पर लगी पाबंदियां हटाने, समुचित दर पर गारंटीशुदा बिजली आपूर्ति करने, किसानों के बकाया कर्ज माफ करने तथा किसानों के लिए पेंशन का प्रावधान करने की मांग की।

# Rise Of Popular Movements जन आंदोलनों का उदय

**Similar demands were made by other farmers' organisations in the country. Shetkari Sanghatana of Maharashtra declared the farmers' movement as a war of Bharat (symbolising rural, agrarian sector) against forces of India (urban industrial sector). You have already studied in Chapter Three that the debate between industry and agriculture has been one of the prominent issues in India's model of development. The same debate came alive once again in the eighties when the agricultural sector came under threat due to economic policies of liberalisation**

एसी माँगें देश के अन्य किसान संगठनों ने भी उठाईं। महाराष्ट्र के शेतकारी संगठन ने किसानों के आंदोलन को 'इंडिया' की ताकतों (यानी शहरी औद्योगिक क्षेत्र) के खिलाफ 'भारत' (यानी ग्रामीण कृषि क्षेत्र) का संग्राम करार दिया। आप तीसरे अध्याय में यह बात पढ़ ही चुके हैं कि भारत में अपनाए गए विकास के मॉडल से जुड़े विवादों में कृषि बनाम उद्योग का विवाद प्रमुख था। यही विवाद अस्सी के दशक में एक बार फिर उठा जब उदारीकरण की आर्थिक नीतियों के कारण कृषि क्षेत्र पर खतरे मँडराने लगे थे।



# Rise Of Popular Movements जन आंदोलनों का उदय

## Characteristics

**Activities conducted by the BKU to pressurise the state for accepting its demands included rallies, demonstrations, sit-ins, and jail bharo (courting imprisonment) agitations. These protests involved tens of thousands of farmers – sometimes over a lakh – from various villages in western Uttar Pradesh and adjoining regions. Throughout the decade of eighties, the BKU organised massive rallies of these farmers in many district headquarters of the State and also at the national capital.**

## विशेषताएँ

सरकार पर अपनी माँगों को मानने के लिए दबाव डालने के क्रम में **BKU** ने रैली, धरना, प्रदर्शन और जेल भरो अभियान का सहारा लिया। इन कार्रवाइयों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उसके आस-पास के इलाके के गाँवों के हज़ारों-हज़ार (कभी-कभी तो एक लाख से भी ज़्यादा) किसानों ने भाग लिया। पूरे अस्सी के दशक भर **BKU** ने राज्य के अनेक जिला मुख्यालयों पर इन किसानों की विशाल रैली आयोजित की। देश की राजधानी दिल्ली में भी **BKU** ने रैली का आयोजन किया।

# Rise Of Popular Movements जन आंदोलनों का उदय

Another novel aspect of these mobilisations was the use of caste linkages of farmers. Most of the BKU members belonged to a single community. The organisation used traditional caste panchayats of these communities in bringing them together over economic issues. In spite of lack of any formal organisation, the BKU could sustain itself for a long time because it was based on clan networks among its members. Funds, resources and activities of BKU were mobilised through these network

इस लामबंदी का एक नया पक्ष यह था कि इसमें किसानों के जातिगत जुड़ाव का इस्तेमाल किया गया था। **BKU** के अधिकांश सदस्य एक खास समुदाय के थे। इस संगठन ने जातिगत समुदायों को आर्थिक मसले पर एकजुट करने के लिए 'जाति-पंचायत' की परंपरागत संस्था का उपयोग किया। किसी औपचारिक सांगठनिक सांगठनिक ढाँचे के अभाव के बावजूद **BKU** अपने को लंबे समय तक कायम रख सका क्योंकि यह संगठन अपने सदस्यों के जातिगत-वंशगत संपर्क-जाल पर आधारित था। **BKU** के लिए धनराशि और संसाधन इन्हीं संपर्कतंत्रों से जुटाए जाते थे और इन्हीं के सहारे **BKU** की गतिविधियां भी संचालित होती थीं।

# Rise Of Popular Movements जन आंदोलनों का उदय

Until the early nineties, the BKU distanced itself from all political parties. It operated as a pressure group in politics with its strength of sheer numbers. The organisation, along with the other farmers' organisations across States, did manage to get some of their economic demands accepted. The farmers' movement became one of the most successful social movements of the 'eighties in this respect. The success of the movement was an outcome of political bargaining powers that its members possessed.

1990 के दशक के शुरुआती सालों तक BKU ने अपने को सभी राजनीतिक दलों से दूर रखा था। यह अपने सदस्यों के संख्या बल के दम पर राजनीति में एक दबाव समूह की तरह सक्रिय था। इस संगठन ने राज्यों में मौजूद अन्य किसान संगठनों को साथ लेकर अपनी कुछ माँगें मनवाने में सफलता पाई। इस अर्थ में किसान आंदोलन अस्सी के दशक में सबसे ज्यादा सफल सामाजिक आंदोलन था। इस आंदोलन की सफलता के पीछे इसके सदस्यों की राजनीतिक मोल-भाव की क्षमता का हाथ था।

# Rise Of Popular Movements जन आंदोलनों का उदय

The movement was active mainly in the prosperous States of the country. Unlike most of the Indian farmers who engage in agriculture for subsistence, members of the organisations like the BKU grew cash crops for the market. Like the BKU, farmers' organisations across States recruited their members from communities that dominated regional electoral politics. Shetkari Sanghatana of Maharashtra and Rayata Sangha of Karnataka, are prominent examples of such organisations of the farmers.

यह आंदोलन मुख्य रूप से देश के समृद्ध राज्यों में सक्रिय था। खेती को अपनी जीविका का आधार बनाने वाले अधिकांश भारतीय किसानों के विपरीत **BKU** से संगठनों के सदस्य बाज़ार के लिए नगदी फ़सल उपजाते थे। **BKU** के समान राज्यों के अन्य किसान संगठनों ने अपने सदस्य उन समुदायों के बीच से बनाए जिनका क्षेत्र की चुनावी राजनीति में रसूख था। महाराष्ट्र का शेतकारी संगठन और कर्नाटक का रैयत संघ ऐसे किसान संगठनों के जीवंत उदाहरण हैं।

# Rise Of Popular Movements जन आंदोलनों का उदय

## Anti-Alcohol Movement

When the BKU was mobilising the farmers of the north, an altogether different kind of mobilisation in the rural areas was taking shape in the southern State of Andhra Pradesh. It was a spontaneous mobilisation of women demanding a ban on the sale of alcohol in their neighbourhoods.

## ताड़ी-विरोधी आंदोलन

जब BKU उत्तर में किसानों को लामबंद कर रहा था उसी समय एक अलग तरह का आंदोलन दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश में आकार ले रहा था। यह महिलाओं का एक स्वतःस्फूर्त आंदोलन था। ये महिलाएँ अपने आस-पड़ोस में मदिरा की बिक्री पर पाबंदी की माँग कर रही थीं।

# Rise Of Popular Movements जन आंदोलनों का उदय

**Stories of this kind appeared in the Telugu press almost daily during the two months of September and October 1992. The name of the village would change in each case but the story was the same. Rural women in remote villages from the State of Andhra Pradesh fought a battle against alcoholism, against mafias and against the government during this period. These agitations shaped what was known as the anti-arrack movement in the State.**

वर्ष 1992 के सितंबर और अक्टूबर माह में इस तरह की खबरें तेलुगु प्रेस में लगभग रोज़ दिखती थी। गाँव का नाम बदल जाता पर खबर वैसी ही होती। ग्रामीण महिलाओं ने शराब के खिलाफ़ लड़ाई छेड़ रखी थी। यह लड़ाई माफ़िया और सरकार दोनों के खिलाफ़ थी। इस आंदोलन ने ऐसा रूप धारण किया कि इसे राज्य में ताड़ी-विरोधी आंदोलन के रूप में जाना गया।

# Rise Of Popular Movements जन आंदोलनों का उदय

## Origins

**In a village in the interior of Dubagunta in Nellore district of Andhra Pradesh, women had enrolled in the Adult Literacy Drive on a large scale in the early nineteen nineties. It is during the discussion in the class that women complained of increased consumption of a locally brewed alcohol – arrack – by men in their families. The habit of alcoholism had taken deep roots among the village people and was ruining their physical and mental health.**

## उदय

आंध्र प्रदेश के नेल्लौर ज़िले के एक दूर-दराज के गाँव दुबरागंटा में 1990 के शुरुआती दौर में महिलाओं के बीच प्रौढ़-साक्षरता कार्यक्रम चलाया गया जिसमें महिलाओं ने बड़ी संख्या में पंजीकरण कराया। कक्षाओं में महिलाएँ घर के पुरुषों द्वारा देशी शराब, ताड़ी आदि पीने की शिकायतें करती थीं। ग्रामीणों को शराब की गहरी लत लग चुकी थी। इसके चलते वे शारीरिक और मानसिक रूप से भी कमजोर हो गए थे।



# Rise Of Popular Movements जन आंदोलनों का उदय

**It affected the rural economy of the region a great deal. Indebtedness grew with increasing scales of consumption of alcohol, men remained absent from their jobs and the contractors of alcohol engaged in crime for securing their monopoly over the arrack trade. Women were the worst sufferers of these illeffects of alcohol as it resulted in the collapse of the family economy and women had to bear the brunt of violence from the male family members, particularly the husband.**

शराबखोरी से क्षेत्र की ग्रामीण अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो रही थी। शराबखोरी के बढ़ने से कर्ज का बोझ बढ़ा। पुरुष अपने काम से लगातार गैर-हाज़िर रहने लगे। शराब के ठेकेदार मदिरा व्यापार पर एकाधिकार बनाये रखने के लिए अपराधों में व्यस्त थे। शराबखोरी से सबसे ज़्यादा दिक्कत महिलाओं को हो रही थी। इससे परिवार की अर्थव्यवस्था चरमराने लगी। परिवार में तनाव और मारपीट का माहौल बनने लगा।



# Rise Of Popular Movements जन आंदोलनों का उदय

**Women in Nellore came together in spontaneous local initiatives to protest against arrack and forced closure of the wine shop. The news spread fast and women of about 5000 villages got inspired and met together in meetings, passed resolutions for imposing prohibition and sent them to the District Collector. The arrack auctions in Nellore district were postponed 17 times. This movement in Nellore District slowly spread all over the State.**

नेल्लोर में महिलाएँ ताड़ी की बिक्री के खिलाफ आगे आई और उन्होंने शराब की दुकानों को बंद कराने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। यह खबर तेज़ी से फैली और करीब 5000 गाँवों की महिलाओं ने आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया। प्रतिबंध संबंधी एक प्रस्ताव को पास कर इसे ज़िला कलेक्टर को भेजा गया। नेल्लोर ज़िले में ताड़ी की नीलामी 17 बार रद्द हुई। नेल्लोर ज़िले का यह आंदोलन धीरे-धीरे पूरे राज्य में फैल गया।

# Rise Of Popular Movements जन आंदोलनों का उदय

## Linkages

**The slogan of the anti-arrack movement was simple – prohibition on the sale of arrack. But this simple demand touched upon larger social, economic and political issues of the region that affected women's life. A close nexus between crime and politics was established around the business of arrack. The State government collected huge revenues by way of taxes imposed on the sale of arrack and was therefore not willing to impose a ban.**

## आंदोलन की कड़ियाँ

ताड़ी-विरोधी आंदोलन का नारा बहुत साधारण था—‘ताड़ी की बिक्री बंद करो।’ लेकिन इस साधारण नारे ने क्षेत्र के व्यापक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों तथा महिलाओं के जीवन को गहरे प्रभावित किया। ताड़ी व्यवसाय को लेकर अपराध एवं राजनीति के बीच एक गहरा नाता बन गया था। राज्य सरकार को ताड़ी की बिक्री से काफ़ी राजस्व की प्राप्ति होती थी इसलिए वह इस पर प्रतिबंध नहीं लगा रही थी।

# Rise Of Popular Movements जन आंदोलनों का उदय

**Groups of local women tried to address these complex issues in their agitation against arrack. They also openly discussed the issue of domestic violence. Their movement, for the first time, provided a platform to discuss private issues of domestic violence. Thus, the anti-arrack movement also became part of the women's movement.**

स्थानीय महिलाओं के समूहों ने इस जटिल मुद्दे को अपने आंदोलन में उठाना शुरू किया। वे घरेलू हिंसा के मुद्दे पर भी खुले तौर पर चर्चा करने लगीं। आंदोलन ने पहली बार महिलाओं को घरेलू हिंसा जैसे निजी मुद्दों पर बोलने का मौका दिया।

# Rise Of Popular Movements जन आंदोलनों का उदय

**Earlier, women's groups working on issues of domestic violence, the custom of dowry, sexual abuse at work and public places were active mainly among urban middle class women in different parts of the country. Their work led to a realisation that issues of injustice to women and of gender inequalities were complicated in nature.**

इस तरह ताड़ी-विरोधी आंदोलन महिला आंदोलन का एक हिस्सा बन गया। इससे पहले घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, कार्यस्थल एवं सार्वजनिक स्थानों पर यौन-उत्पीड़न के खिलाफ काम करने वाले महिला समूह आमतौर पर शहरी मध्यवर्गीय महिलाओं के बीच ही सक्रिय थे और यह बात पूरे देश पर लागू होती थी। महिला समूहों के सतत प्रयास से यह समझदारी विकसित होनी शुरू हुई कि औरतों पर होने वाले अत्याचार और लैंगिक भेदभाव का मामला खासा जटिल है।

# **Rise Of Popular Movements** जन आंदोलनों का उदय

**During the decade of the eighties women's movement focused on issues of sexual violence against women – within the family and outside. These groups ran a campaign against the system of dowry and demanded personal and property laws based on the norms of gender equality.**

आठवें दशक के दौरान महिला आंदोलन परिवार के अंदर और उसके बाहर होने वाली यौन हिंसा के मुद्दों पर केंद्रित रहा। इन समूहों ने दहेज प्रथा के खिलाफ मुहिम चलाई और लैंगिक समानता के सिद्धांत पर आधारित व्यक्तिगत एवं संपत्ति कानूनों की माँग की।

# Rise Of Popular Movements जन आंदोलनों का उदय

**These campaigns contributed a great deal in increasing overall social awareness about women's questions. Focus of the women's movement gradually shifted from legal reforms to open social confrontations like the one we discussed above. As a result the movement made demands of equal representation to women in politics during the nineties. We know that 73rd and 74th amendments have granted reservations to women in local level political offices.**

इस तरह के अभियानों ने महिलाओं के मुद्दों के प्रति समाज में व्यापक जागरूकता पैदा की। धीरे-धीरे महिला आंदोलन कानूनी सुधारों से हटकर सामाजिक टकराव के मुद्दों पर भी खुले तौर पर बात करने लगा। ऊपर हमने एक ऐसे ही विषय पर बातें की हैं। नवें दशक तक आते-आते महिला आंदोलन समान राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात करने लगा था। आपको ज्ञात ही होगा कि संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के अंतर्गत महिलाओं को स्थानीय राजनीतिक निकायों में आरक्षण दिया गया है।

# **Rise Of Popular Movements** जन आंदोलनों का उदय

**Demands for extending similar reservations in State and Central legislatures have also been made. A constitution amendment bill to this effect has been proposed but has not received enough support from the Parliament yet. Main opposition to the bill has come from groups, including some women's groups, who are insisting on a separate quota for Dalit and OBC women within the proposed women's quota in higher political offices.**

इस व्यवस्था को राज्यों की विधानसभाओं तथा संसद में भी लागू करने की माँग की जा रही है। संसद में इस आशय का एक संशोधन विधेयक भी पेश किया जा चुका है। परंतु विधेयक को अभी तक ज़रूरी समर्थन हासिल नहीं हो पाया है। कुछ गुट जिनमें महिला समूह भी शामिल हैं, प्रस्तुत विधेयक के अंतर्गत दलित और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की माँग कर रहे हैं।



# Rise Of Popular Movements जन आंदोलनों का उदय

## Narmada Bachao Aandolan

**Social movements that we discussed so far raised various issues about the model of economic development that India had adopted at the time of Independence. Chipko movement brought out the issue of ecological depletion whereas the farmers complained of neglect of agricultural sector. Social and material conditions of Dalits led to their mass struggles whereas the anti-arrack movement focused on the negative fallouts of what was considered development. The issue implicit in all these movements was made explicit by the movements against displacement caused by huge developmental projects.**

## नर्मदा बचाओ आंदोलन

वे सभी सामाजिक आंदोलन जिनके बारे में हमने अभी तक चर्चा की है, देश में आज़ादी के बाद अपनाए गए आर्थिक विकास के मॉडल पर सवालिया निशान लगाते रहे हैं। एक ओर जहां चिपको आंदोलन ने इस मॉडल में निहित पर्यावरणीय विनाश के मुद्दे को सामने रखा, वहीं दूसरी ओर, किसानों ने कृषि क्षेत्र की अनदेखी पर रोष प्रकट किया। इसी तरह जहां दलित समुदायों की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियां उन्हें जन-संघर्षों की ओर ले गई वहीं ताड़ी-बंदी आंदोलन ने विकास के नकारात्मक पहलुओं की ओर इशारा किया।

# Rise Of Popular Movements जन आंदोलनों का उदय

## Sardar Sarovar Project

**An ambitious developmental project was launched in the Narmada valley of central India in early 'eighties. The project consisted of 30 big dams, 135 medium sized and around 3,000 small dams to be constructed on the Narmada and its tributaries that flow across three states of Madhya Pradesh, Gujarat and Maharashtra. Sardar Sarovar Project in Gujarat and the Narmada Sagar Project in Madhya Pradesh were two of the most important and biggest, multi-purpose dams planned under the project. Narmada Bachao Aandolan, a movement to save Narmada, opposed the construction of these dams and questioned the nature of ongoing developmental projects in the country.**

## सरदार सरोवर परियोजना

आठवें दशक के प्रारंभ में भारत के मध्य भाग में स्थित नर्मदा घाटी में विकास परियोजना के तहत मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से गुज़रने वाली नर्मदा और उसकी सहायक नदियों पर 30 बड़े, 135 मझोले तथा 300 छोटे बाँध बनाने का प्रस्ताव रखा गया। गुजरात के सरदार सरोवर और मध्य प्रदेश के नर्मदा सागर बाँध के रूप में दो सबसे बड़ी और बहु-उद्देश्यीय परियोजनाओं का निर्धारण किया गया। नर्मदा नदी के बचाव में नर्मदा बचाओ आंदोलन चला। इस आंदोलन ने बाँधों के निर्माण का विरोध किया। नर्मदा बचाओ आंदोलन इन बाँधों के निर्माण के साथ-साथ देश में चल रही विकास परियोजनाओं के औचित्य पर भी सवाल उठाता रहा है।

# Rise Of Popular Movements जन आंदोलनों का उदय

**Sardar Sarovar Project is a multipurpose mega-scale dam. Its advocates say that it would benefit huge areas of Gujarat and the three adjoining states in terms of availability of drinking water and water for irrigation, generation of electricity and increase in agricultural production. Many more subsidiary benefits like effective flood and drought control in the region were linked to the success of this dam.**

सरदार सरोवर परियोजना के अंतर्गत एक बहु-उद्देश्यीय विशाल बाँध बनाने का प्रस्ताव है। बाँध समर्थकों का कहना है कि इसके निर्माण से गुजरात के एक बहुत बड़े हिस्से सहित तीन पड़ोसी राज्यों में पीने के पानी, सिंचाई और बिजली के उत्पादन की सुविधा मुहैया कराई जा सकेगी तथा कृषि की उपज में गुणात्मक बढ़ोतरी होगी। बाँध की उपयोगिता इस बात से भी जोड़कर देखी जा रही थी कि इससे बाढ़ और सूखे की आपदाओं पर अंकुश लगाया जा सकेगा।

# **Rise Of Popular Movements** जन आंदोलनों का उदय

**In the process of construction of the dam 245 villages from these States were expected to get submerged. It required relocation of around two and a half lakh people from these villages. Issues of relocation and proper rehabilitation of the project-affected people were first raised by local activist groups. It was around 1988-89 that the issues crystallised under the banner of the NBA – a loose collective of local voluntary organisations.**

प्रस्तावित बाँध के निर्माण से संबंधित राज्यों के 245 गाँव डूब के क्षेत्र में आ रहे थे। अतः प्रभावित गाँवों के करीब ढाई लाख लोगों के पुनर्वास का मुद्दा सबसे पहले स्थानीय कार्यकर्ताओं ने उठाया। इन गतिविधियों को एक आंदोलन की शक्ल 1988-89 के दौरान मिली जब कई स्थानीय स्वयंसेवी संगठनों ने खुद को नर्मदा बचाओ आंदोलन के रूप में गठित किया।

# Rise Of Popular Movements जन आंदोलनों का उदय

## Debates and struggles

**Since its inception the NBA linked its opposition to the Sardar Sarovar Project with larger issues concerning the nature of ongoing developmental projects, efficacy of the model of development that the country followed and about what constituted public interest in a democracy. It demanded that there should be a costbenefit analysis of the major developmental projects completed in the country so far.**

## वाद-विवाद और संघर्ष

नर्मदा आंदोलन अपने गठन की शुरुआत से ही सरदार सरोवर परियोजना को विकास परियोजनाओं के बृहत्तर मुद्दों से जोड़कर देखता रहा है। यह आंदोलन विकास के मॉडल और उसके सार्वजनिक औचित्य पर सवाल उठाता रहा है। आंदोलन की एक मुख्य दलील यह रही है कि अब तक की सभी विकास परियोजनाओं पर हुए खर्च का विश्लेषण किया जाए।

# Rise Of Popular Movements जन आंदोलनों का उदय

**The movement argued that larger social costs of the developmental projects must be calculated in such an analysis. The social costs included forced resettlement of the project-affected people, a serious loss of their means of livelihood and culture and depletion of ecological resources.**

आंदोलन के अनुसार परियोजनाओं के लागत विश्लेषण में इस बात का जायजा भी लिया जाना चाहिए कि समाज के विभिन्न वर्गों को इन परियोजनाओं का क्या खामियाजा भुगतना पड़ा है! आंदोलन के नेतृत्व ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि इन परियोजनाओं का लोगों के पर्यावास, आजीविका, संस्कृति तथा पर्यावरण पर बुरा असर पड़ा है।

# Rise Of Popular Movements जन आंदोलनों का उदय

**Initially the movement demanded proper and just rehabilitation of all those who were directly or indirectly affected by the project. The movement also questioned the nature of decision-making processes that go in the making of mega scale developmental projects. The NBA insisted that local communities must have a say in such decisions and they should also have effective control over natural resources like water, land and forests.**

शुरुआत में आंदोलन ने यह माँग रखी कि परियोजना से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित सभी लोगों का समुचित पुनर्वास किया जाए। आंदोलन के लोगों ने इन महाकाय विकास परियोजनाओं के निर्माण की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। नर्मदा बचाओ आंदोलन ने इस बात पर ज़ोर दिया कि ऐसी परियोजनाओं की निर्णय प्रक्रिया में स्थानीय समुदायों की भागीदारी होनी चाहिए और जल, जंगल, ज़मीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर उनका प्रभावी नियंत्रण होना चाहिए।



# **Rise Of Popular Movements** जन आंदोलनों का उदय

**The movement also asked why, in a democracy, should some people be made to sacrifice for benefiting others. All these considerations led the NBA to shift from its initial demand for rehabilitation to its position of total opposition to the dam.**

आंदोलन ने एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी उठाया कि लोकतंत्र में कुछ लोगों के लाभ के लिए अन्य लोगों को नुकसान क्यों उठाना चाहिए? इस तरह के सवालों से जूझते हुए आंदोलन ने अंततः पुनर्वास की माँग से आगे कदम बढ़ाया। अब आंदोलन बड़े बाँधों की खुली मुखालफ़त करता है।

# **Rise Of Popular Movements** जन आंदोलनों का उदय

**Arguments and agitations of the movement met vociferous opposition in the States benefiting from the project, especially in Gujarat. At the same time, the point about right to rehabilitation has been now recognised by the government and the judiciary. A comprehensive National Rehabilitation Policy formed by the government in 2003 can be seen as an achievement of the movements like the NBA.**

नर्मदा बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ताओं का गुजरात जैसे राज्यों में तीव्र विरोध हुआ है। परंतु अब सरकार और न्यायपालिका दोनों ही यह स्वीकार करते हैं कि लोगों को पुनर्वास मिलना चाहिए। सरकार द्वारा 2003 में स्वीकृत राष्ट्रीय पुनर्वास नीति को नर्मदा बचाओ जैसे सामाजिक आंदोलन की उपलब्धि के रूप में देखा जा सकता है। परंतु सफलता के साथ ही नर्मदा बचाओ आंदोलन को बाँध के निर्माण पर रोक लगाने की माँग उठाने पर तीखा विरोध भी झलना पड़ा है।

# Rise Of Popular Movements जन आंदोलनों का उदय

**However, its demand to stop the construction of the dam was severely criticised by many as obstructing the process of development, denying access to water and to economic development for many. The Supreme Court upheld the government's decision to go ahead with the construction of the dam while also instructing to ensure proper rehabilitation.**

आलोचकों का कहना है कि आंदोलन का अडियल रवैया विकास की प्रक्रिया, पानी की उपलब्धता और आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सरकार को बाँध का काम आगे बढ़ाने की हिदायत दी है लेकिन साथ ही उसे यह आदेश भी दिया गया है कि प्रभावित लोगों का पुनर्वास सही ढंग से किया जाए!

# Rise Of Popular Movements जन आंदोलनों का उदय

**Narmada Bachao Aandolan continued a sustained agitation for more than twenty years. It used every available democratic strategy to put forward its demands. These included appeals to the judiciary, mobilisation of support at the international level, public rallies in support of the movement and a revival of forms of Satyagraha to convince people about the movement's position. However, the movement could not garner much support among the mainstream political parties – including the opposition parties.**

नर्मदा बचाओ आंदोलन दो से भी ज्यादा दशकों तक चला। आंदोलन ने अपनी माँग मुखर करने के लिए हरसंभव लोकतांत्रिक रणनीति का इस्तेमाल किया। आंदोलन ने अपनी बात न्यायपालिका से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक से उठाई। आंदोलन की समझ को जनता के सामने मुखर करने के लिए नेतृत्व ने सार्वजनिक रैलियों तथा सत्याग्रह जैसे तरीकों का भी प्रयोग किया परंतु विपक्षी दलों सहित मुख्यधारा की राजनीतिक पार्टियों के बीच आंदोलन कोई खास जगह नहीं बना पाया।

# Rise Of Popular Movements जन आंदोलनों का उदय

**In fact, the journey of the Narmada Bachao Aandolan depicted a gradual process of disjunction between political parties and social movements in Indian politics. By the end of the 'nineties, however, the NBA was not alone. There emerged many local groups and movements that challenged the logic of large scale developmental projects in their areas. Around this time, the NBA became part of a larger alliance of people's movements that are involved in struggles for similar issues in different regions of the country.**

वास्तव में, नर्मदा आंदोलन की विकास रेखा भारतीय राजनीति में सामाजिक आंदोलन और राजनीतिक दलों के बीच निरंतर बढ़ती दूरी को बयान करती है। उल्लेखनीय है कि नवें दशक के अंत तक पहुँचते-पहुँचते नर्मदा बचाओ आंदोलन से कई अन्य स्थानीय समूह और आंदोलन भी आ जुड़े। ये सभी आंदोलन अपने-अपने क्षेत्रों में विकास की बृहत् परियोजनाओं का विरोध करते थे। इस मुकाम तक आते-आते नर्मदा बचाओ आंदोलन देश के विभिन्न हिस्सों में चल रहे समधर्मा आंदोलनों के गठबंधन का अंग बन गया।

# Rise Of Popular Movements जन आंदोलनों का उदय

## Lesson from popular movements

**The history of these popular movements helps us to understand better the nature of democratic politics. We have seen that these non-party movements are neither sporadic in nature nor are these a problem. These movements came up to rectify some problems in the functioning of party politics and should be seen as integral part of our democratic politics. They represented new social groups whose economic and social grievances were not redressed in the realm of electoral politics.**

## जन आंदोलन के सबक

जन आंदोलनों का इतिहास हमें लोकतांत्रिक राजनीति को बेहतर ढंग से समझने में मदद देता है। हमने देखा कि इस तरह के गैर-दलीय आंदोलन अनियमित ढंग से खड़े नहीं हो जाते। उन्हें समस्या के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। इन आंदोलनों का उद्देश्य दलीय राजनीति की खामियों को दूर करना था। इस रूप में, इन आंदोलनों को देश की लोकतांत्रिक राजनीति के अहम हिस्से के तौर पर देखा जाना चाहिए।

# Rise Of Popular Movements जन आंदोलनों का उदय

**Popular movements ensured effective representation of diverse groups and their demands. This reduced the possibility of deep social conflict and disaffection of these groups from democracy. Popular movements suggested new forms of active participation and thus broadened the idea of participation in Indian democracy.**

सामाजिक आंदोलनों ने समाज के उन नए वर्गों की सामाजिक-आर्थिक समस्याओं को अभिव्यक्ति दी जो अपनी दिक्कतों को चुनावी राजनीति के जरिए हल नहीं कर पा रहे थे। विभिन्न सामाजिक समूहों के लिए ये आंदोलन अपनी बात रखने का बेहतर माध्यम बनकर उभरे। समाज के गहरे तनावों और जनता के क्षोभ को एक सार्थक दिशा देकर इन आंदोलनों ने एक तरह से लोकतंत्र की रक्षा की है। सक्रिय भागीदारी के नए रूपों के प्रयोग ने भारतीय लोकतंत्र के जनाधार को बढ़ाया है।



# Rise Of Popular Movements जन आंदोलनों का उदय

**Critics of these movements often argue that collective actions like strikes, sit-ins and rallies disrupt the functioning of the government, delay decision making and destabilise the routines of democracy. Such an argument invites a deeper question: why do these movements resort to such assertive forms of action? We have seen in this chapter that popular movements have raised legitimate demands of the people and have involved large scale participation of citizens.**

इन आंदोलनों के आलोचक अक्सर यह दलील देते हैं कि हड़ताल, धरना और रैली जैसी सामूहिक कार्रवाईयों से सरकार के कामकाज पर बुरा असर पड़ता है। उनके अनुसार इस तरह की गतिविधियों से सरकार की निर्णय-प्रक्रिया बाधित होती है तथा रोज़मर्रा की लोकतांत्रिक व्यवस्था भंग होती है। इस तरह की दलीलें एक और गहरे सवाल को जन्म देती हैं और वह सवाल यह है कि जन आंदोलन ऐसी मुखर सामूहिक गतिविधियों का सहारा क्यों लेते हैं? इस अध्याय में हमने देखा कि ये जन आंदोलन जनता की जायज़ माँगों के नुमाइंदा बनकर उभरे हैं और उन्होंने नागरिकों के एक बड़े समूह को अपने साथ जोड़ने में कामयाबी हासिल की है।

# Rise Of Popular Movements जन आंदोलनों का उदय

**It should be noted that the groups mobilised by these movements are poor, socially and economically disadvantaged sections of the society from marginal social groups. The frequency and the methods used by the movements suggest that the routine functioning of democracy did not have enough space for the voices of these social groups. That is perhaps why these groups turned to mass actions and mobilisations outside the electoral arena.**

हमें यहां इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि इन जन आंदोलनों द्वारा लामबंद की जाने वाली जनता सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित तथा अधिकारहीन वर्गों से संबंध रखती है। जन आंदोलनों द्वारा अपनाए गए तौर-तरीकों से ज़ाहिर होता है कि रोज़मर्रा की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इन वंचित समूहों को अपनी बात कहने का पर्याप्त मौका नहीं मिलता था। इसी कारण ये समूह चुनावी शासन-भूमि से अलग जन-कार्रवाई और लामबंदी की रणनीति अपनाते हैं।

# Rise Of Popular Movements जन आंदोलनों का उदय

**This can be seen in the recent case of the new economic policies. As you will read in Chapter Nine, there is a growing consensus among political parties over the implementation of these policies. It follows that those marginal social groups who may be adversely affected by these policies get less and less attention from political parties as well as the media. Therefore, any effective protest against these policies involves assertive forms of action that are taken up by the popular movements outside the framework of political parties.**

यह बात हाल की नयी आर्थिक नीतियों के मामले में देखी जा सकती है। आप नौवें अध्याय में पढ़ेंगे कि कमोबेश सभी राजनीतिक दल इन नीतियों को लागू करने के पक्ष में हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हाशिए पर मौजूद जिन सामाजिक समूहों पर आर्थिक नीतियों का दुष्प्रभाव पड़ सकता है उन पर ये राजनीतिक दल खास ध्यान नहीं देंगे और न ही मुख्यधारा की मीडिया उन पर ध्यान देगी। ऐसे में नयी आर्थिक नीतियों का विरोध करना हो तो जन-कार्रवाई का ही रास्ता बचता है। जन आंदोलन यही काम करते हैं। वे राजनीतिक दलों के चालू मुहावरे से अलग अपने मुद्दे उठाते हैं।

# Rise Of Popular Movements जन आंदोलनों का उदय

**Movements are not only about collective assertions or only about rallies and protests. They involve a gradual process of coming together of people with similar problems, similar demands and similar expectations. But then movements are also about making people aware of their rights and the expectations that they can have from democratic institutions. Social movements in India have been involved in these educative tasks for a long time and have thus contributed to expansion of democracy rather than causing disruptions. The struggle for the right to information is a case in point.**

आंदोलन का मतलब सिर्फ धरना-प्रदर्शन या सामूहिक कार्रवाई नहीं होता। इसके अंतर्गत किसी समस्या से पीड़ित लोगों का धीरे-धीरे एकजुट होना और समान अपेक्षाओं के साथ एक-सी माँग उठाना ज़रूरी है। इसके अतिरिक्त, आंदोलन का एक काम लोगों को अपने अधिकारों को लेकर जागरूक बनाना भी है ताकि लोग यह समझें कि लोकतंत्र की संस्थाओं से वे क्या-क्या उम्मीद कर सकते हैं। भारत के सामाजिक आंदोलन बहुत दिनों से जनता को जागरूक बनाने के इस काम में संलग्न हैं। ऐसे में इन आंदोलनों ने लोकतंत्र को बाधा नहीं पहुँचायी बल्कि उसका विस्तार किया है।

# Rise Of Popular Movements जन आंदोलनों का उदय

**Yet the real life impact of these movements on the nature of public policies seems to be very limited. This is partly because most of the contemporary movements focus on a single issue and represent the interest of one section of society. Thus it becomes possible to ignore their reasonable demands. Democratic politics requires a broad alliance of various disadvantaged social groups. Such an alliance does not seem to be shaping under the leadership of these movements. Political parties are required to bring together different sectional interests, but they also seem to be unable to do so.**

कितु कुल मिलाकर सार्वजनिक नीतियों पर इन आंदोलनों का असर काफी सीमित रहा है। इसका एक कारण तो यह है कि समकालीन सामाजिक आंदोलन किसी एक मुद्दे के इर्द-गिर्द ही जनता को लामबंद करते हैं। इस तरह वे समाज के किसी एक वर्ग का ही प्रतिनिधित्व कर पाते हैं। इसी सीमा के चलते सरकार इन आंदोलनों की जायज़ माँगों को ठुकराने का साहस कर पाती है। लोकतांत्रिक राजनीति वंचित वर्गों के व्यापक गठबंधन को लेकर ही चलती है जबकि जन आंदोलनों के नेतृत्व में यह बात संभव नहीं हो पाती। राजनीतिक दलों को जनता के विभिन्न वर्गों के बीच सामंजस्य बैठाना पड़ता है, जबकि जन आंदोलनों का नेतृत्व इस वर्गीय हित के प्रश्न को कायदे से नहीं सँभाल पाता।

# Rise Of Popular Movements जन आंदोलनों का उदय

**Parties do not seem to be taking up issues of marginal social groups. The movements that take up these issues operate in a very restrictive manner. The relationship between popular movements and political parties has grown weaker over the years, creating a vacuum in politics. In the recent years, this has become a major problem in Indian politics.**

हित के प्रश्न को कायदे से नहीं सँभाल पाता। जान पड़ता है कि राजनीतिक दलों ने समाज के वंचित और अधिकारहीन लोगों के मुद्दों पर ध्यान देना छोड़ दिया है। पर जन आंदोलन का नेतृत्व भी ऐसे मुद्दों को सीमित ढंग से ही उठा पाता है। विगत वर्षों में राजनीतिक दलों और जन आंदोलनों का आपसी संबंध कमजोर होता गया है। इससे राजनीति में एक सूनेपन का माहौल पनपा है। हाल के वर्षों में, भारत की राजनीति में यह एक बड़ी समस्या के रूप में उभरा है।

# Rise Of Popular Movements जन आंदोलनों का उदय

## **Movement for Right to Information**

**The movement for Right to Information (RTI) is one of the few recent examples of a movement that did succeed in getting the state to accept its major demand. The movement started in 1990, when a mass based organisation called the Mazdoor Kisan Shakti Sangathan (MKSS) in Rajasthan took the initiative in demanding records of famine relief work and accounts of labourers. The demand was first raised in Bhim Tehsil in a very backward region of Rajasthan.**

## **सूचना के अधिकार का आंदोलन**

सूचना के अधिकार का आंदोलन जन आंदोलनों की सफलता का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। यह आंदोलन सरकार से एक बड़ी माँग को पूरा कराने में सफल रहा है। इस आंदोलन की शुरुआत 1990 में हुई और इसका नेतृत्व किया मज़दूर किसान शक्ति संगठन (MKSS) ने। राजस्थान में काम कर रहे इस संगठन ने सरकार के सामने यह माँग रखी कि अकाल राहत कार्य और मज़दूरों को दी जाने वाली पगार के रिकॉर्ड का सार्वजनिक खुलासा किया जाए। यह माँग राजस्थान के एक बेहद पिछड़े इलाके—भीम तहसील में सबसे पहले उठाई गई थी।



# Rise Of Popular Movements जन आंदोलनों का उदय

**The villagers asserted their right to information by asking for copies of bills and vouchers and names of persons on the muster rolls who have been paid wages on the construction of schools, dispensaries, small dams and community centres. On paper such development projects were all completed, but it was common knowledge of the villagers that there was gross misappropriation of funds. In 1994 and 1996, the MKSS organised Jan Sunwais or Public Hearings, where the administration was asked to explain its stand in public.**

इस मुहिम के तहत ग्रामीणों ने प्रशासन से अपने वेतन और भुगतान के बिल उपलब्ध कराने को कहा। दरअसल, इन लोगों को लग रहा था कि स्कूलों, डिस्पेंसरी, छोटे बाँधों तथा सामुदायिक केंद्रों के निर्माण कार्य के दौरान उन्हें दी गई मज़दूरी में भारी घपला हुआ है। कहने के लिए ये विकास परियोजनाएँ पूरी हो गई थीं लेकिन लोगों का मानना था कि सारे काम में धन की हेराफेरी हुई है। पहले 1994 और उसके बाद 1996 में मज़दूर किसान शक्ति संगठन ने जन-सुनवाई का आयोजन किया और प्रशासन को इस मामले में अपना पक्ष स्पष्ट करने को कहा।

# Rise Of Popular Movements जन आंदोलनों का उदय

**The movement had a small success when they could force an amendment in the Rajasthan Panchayati Raj Act to permit the public to procure certified copies of documents held by the Panchayats. The Panchayats were also required to publish on a board and in newspapers the budget, accounts, expenditure, policies and beneficiaries. In 1996 MKSS formed National Council for People's Right to Information in Delhi to raise RTI to the status of a national campaign.**

आंदोलन के दबाव में सरकार को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करना पड़ा। नए कानून के तहत जनता को पंचायत के दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने की अनुमति मिल गई। संशोधन के बाद पंचायतों के लिए बजट, लेखा, खर्च, नीतियों और लाभार्थियों के बारे में सार्वजनिक घोषणा करना अनिवार्य कर दिया गया। अब पंचायतों को इन मदों के बारे में नोटिस बोर्ड या अखबारों में सूचना देनी होती है। 1996 में **MKSS** ने दिल्ली में सूचना के अधिकार को लेकर राष्ट्रीय समिति का गठन किया।

# **Rise Of Popular Movements** जन आंदोलनों का उदय

**Prior to that, the Consumer Education and Research Center, the Press Council and the Shourie committee had proposed a draft RTI law. In 2002, a weak Freedom of Information Act was legislated but never came into force. In 2004 RTI Bill was tabled and received presidential assent in June 2005.**

इस कार्रवाई का लक्ष्य सूचना के अधिकार को राष्ट्रीय अभियान का रूप देना था। इससे पहले, **Consumer Education and Research Center** (उपभोक्ता शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र), **Press Council** तथा शौरी समिति ने सूचना के अधिकार का एक मसौदा तैयार किया था। 2002 में 'सूचना की स्वतंत्रता' नाम का एक विधेयक पारित हुआ था। यह एक कमजोर अधिनियम था और इसे अमल में नहीं लाया गया। सन् 2004 में सूचना के अधिकार के विधेयक को सदन में रखा गया। जून 2005 में विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी हासिल हुई।